



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (B)
PART II—Section 3—Sub-section (B)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 524]
No. 524]

नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, सितम्बर 19, 1996/भाद्र 28, 1918
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 1996/BHADRA 28, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 12 (आर. ई.) /92-97

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1996

का. आ. 642 (अ.).—विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यथासंशोधित निर्यात एवं आयात नीति, 1992-97 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

अध्याय-12 में पैराग्राफ 140-ख के बाद निम्नलिखित नया पैरा 140-ग जोड़ा जाएगा :—

“राज्य 140-ग उपर उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, सम्बन्धित नियम को केवल निर्यात सदन के रूप में मान्यता दी जा सकती है, चाहे मान्यता के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ 138, 139, 139-क, 139-ख और 140 के साथ पठित पैराग्राफ 137 में निर्धारित प्रक्रिया पूरी न की गई हो। यह सुविधा केवल उस अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के साथ होगी जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी।”

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं. 1/12/6/96-97/पीसी-2]

ए./-

श्यामल धोष,

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

2263 GI/96

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION No.12 (RE)/92-97

New Delhi, the 19th September, 1996

S.O. 642 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendments in the Export and Import Policy, 1992-97, as amended.

In Chapter XII, the following new paragraph 140C shall be added after paragraph 140B :—

“State 140C Notwithstanding anything mentioned above, one State Corporation nominated by the respective State Governments/Union Territories may be recognised as an Export House only, even though the criterion for recognition, as laid down in paragraph 137 read with paragraphs 138, 139, 139A, 139B and 140 above, is not fulfilled. This benefit shall be available only for the period and in accordance with such terms and conditions, as may be specified from time to time.”

2. This issues in the public interest.

[F.No.1/12/6/96-97/PC-II]

Sd/-

SHYAMAL GHOSH,
Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.

